(ग) क्या सदूर समिति की सभी सिफारिशों को अब तक लागू कर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को मासिक भत्ते पर काम के निर्धारित घंटों के आधार पर अंशकालिक तौर पर नियुक्त किया जाता है ; इनकी सेवाओं को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमित नहीं किया जाता है । तथापि ये कर्मचारी भर्ती के अनुसार खाली स्थान उपलब्ध होने पर परीक्षा द्वारा वर्ग "घ" /पोस्टमैन और मेलगार्ड के पदों पर नियुक्ति के पात्र होते हैं । अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित करने का अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है । अत: दिल्ली सर्किल के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के पेट्रोलियम सह-उत्पाद

2657. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के पेट्रोलियम सह-उत्पादों के प्रयोग की क्या स्थिति है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : बरौनी रिफाइनरी में कोई उपोत्पाद नहीं है क्योंकि कच्चे तेल के प्रोसेस के दौरान प्राप्त सभी स्ट्रीमों को सीधे या मिश्रण/पुनः संसाधन द्वारा तैयार उत्पादों में बदल दिया जाता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

2658. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन ऐसे कितने तथा कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं तथा जिनमें इस प्रकार की समितियां नहीं है;

(ख) उन गैर-सरकारी सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें इन समितियों में प्रेक्षक के रूप में नामित किया गया है तथा वे समितियां कौन-कौन सी हैं जिनमें इस प्रकार के सदस्य नहीं हैं, उसके कारण क्या-क्या हैं तथा प्रेक्षक कब तक नामित कर दिये जाएंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन समितियों में अध्यक्ष और सदस्य अपने-आप में राजभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं और यदि वे इसका उपयोग करते हैं तो वे कितना-कितना प्रतिशत कार्य राजभाषा में करते हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और जो भी उपलब्ध होगी सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बिहार में अतिरिक्त विभागीय डाक सेवा

2659. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितने-कितने अतिरिक्त विभागीय डाक घर तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है तथा अतिरिक्त विभागीय डाकपालों का वेतन तो डाकघर के भवन के किराए से भी कम है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) बिहार राज्य में अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या 9,484 है।

बिहार राज्य में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या 22,397 है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी अंशकालिक कर्मचारी होते हैं जो मुख्यत: देश के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डाक संबंधी कार्य करते हैं। ये कर्मचारी प्रतिदिन प्राय: 2 से 5 घंटे तक काम करते हैं। ये कर्मचारी जो भी कार्य करते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए, इन्हें न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच भत्ते दिए जाते हैं। डाकघर भवनों को देय किराये का अतिरिक्त विभागीय पोस्ट मास्टरों को दिए जाने वाले भत्तों से कोई संबंध नहीं है।

Power based Industries in Rural Areas

2660. SHRI V. NARAYANASWAMY; Will the Minister of ENERGY be pleased to state;

(a) whether it is a fact that Government have been liberally allowing the co-operative sector power based industries in rural areas of the country to meet the demands of the rural population; and

(b) if so, what are the salient features of the said shceme and by when it will be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Anomaly in the payment of D.A. to Employees

2661. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a difference between the dearness allowance paid to public sector employees and the Central Government employees; and

(b) if so, what action Government propose to take to remove the disparity which is causing unrest among the Public Sector Employees?

THE MINISTER OF INDUSTRY" (SHRr J. VENGAL RAO): (a) Yes, Sir.

(b) Government policy is that all public sector employees should be governed by the Industrial DA pattern. Government's directions to public sector employees to switch over to the Industrial DA pattern has been challenged in the Supreme Court. As per the direction of the Supreme Court a High Power Pay Committee has been constituted to go into the various aspects relating to pay scales and other incidental matters such as additional DA, interim relief and other allowances relating to employees working in the public sector governed by Central Government pattern pay scale and D.A.

बिहार में डाक-तार सेवाएं

2662. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मुंगेर जिले में डाक-तार सेवाओं के विकास में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) एस०टी०डी० आदि की सुविधाओं में कहां तक विस्तार किया गया ;

(ग) डाक-घरों की सुविधा में कहां तक विस्तार किया गया ;